PRESS CLUB OF INDIA
ROAD, NEW DELHI - 110 001, INDIA
ndia1@gmail.com, Web : pressclubofindia.org
Phone : 23719844
23730248
23357048

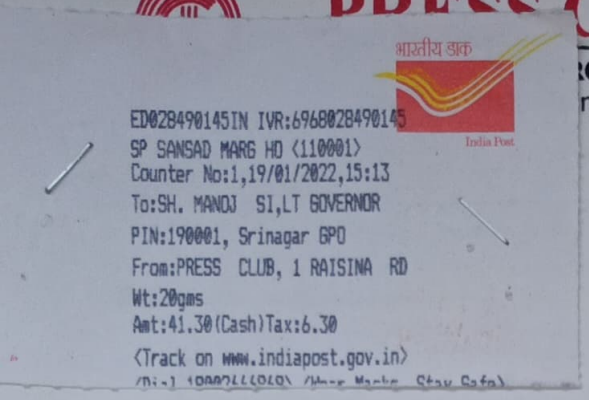

Dated .....
दिनांक: 19/01/2022

श्री मनोज सिन्हा जी,
माननीय उपराज्यपाल,
जम्मू-कश्मीर |

विषय - कश्मीर प्रेस क्लब का रजिस्ट्रेशन, भूमि व भवन आबंटन तत्काल बहाल करने की अपील

आदरणीय मनोज सिन्हा जी,

शनिवार दिनांक 14 जनवरी, 2022 को कश्मीर प्रेस कल्ब परिसर पर हथियारबंद सुरक्षा कर्मियों के ज़रिए प्रशासन द्वारा जिस तरह जबरन कब्ज़ा किया गया, वह बेहद दुखद घटनाक्रम है| कश्मीर प्रेस क्लब के करीब 350 सदस्य हैं| इनमें से ज़्यादातर पत्रकार राष्ट्रीय व राज्य स्तर के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल मीडिया संस्थानों से जुड़े हैं|

आप अवगत ही हैं कि वहां के पत्रकार कश्मीर घाटी में कठिन व नाजुक चुनौतियों के बीच पत्रकारिता कर रहे हैं| वहां के पत्रकारों की पेशेवर दक्षता की बदौलत ही राज्य के घटनाक्रमों, सरकार की उपलब्धियों व विकास कार्यों की जानकारी आम जनता, देश और बाहरी दुनिया को मिल पाती है|

देशभर और तमाम राष्ट्रीय व राज्यों के पत्रकार संगठनों के अलावा एडिटर्स गिल्ड ऑफ़ इंडिया, प्रेस क्लब ऑफ़ इंडिया व दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स समेत देशभर के पत्रकारों व संपादकों ने कश्मीर प्रेस क्लब पर प्रशासन की इस कार्रवाई पर अपना विरोध व्यक्त किया है| आश्चर्य यह है कि यह सब कुछ कश्मीर प्रेस क्लब के निर्वाचित पदाधिकारियों को बिना पूर्व सूचना के किया गया|

प्रेस क्लब ऑफ़ इंडिया की मैनेजिंग कमेटी इस बात से काफ़ी चिंतित है कि रविवार 16 जनवरी 2022 को आपसे की गयी हम सभी की अपील का स्थानीय प्रशासन ने कोई संज्ञान तक नहीं लिया| इसके बजाय पहले दिन ही प्रशासन द्वारा कश्मीर प्रेस क्लब को आवंटित भूमि व भवन का आवंटन हड़बड़ी में निरस्त करने की एकतरफा कार्रवाई कर दी गयी| इसके लिए पूर्व नोटिस देने या अपना पक्ष रखने का अवसर तक नहीं दिया गया|

हमारा मानना है कि कश्मीर प्रेस क्लब का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर प्रशासन द्वारा कुछ लोगों को निर्वाचित पदाधिकारियों को हटाकर क्लब की सुपुर्दगी देना अनुचित व अवैध कार्रवाई है| प्रेस क्लब का भू आवंटन और परिसर को राज्य संपदा विभाग के कब्जे में लेना व लोकतांत्रिक ढंग से प्रेस संगठन संचालित के स्थानीय पत्रकारों के बुनियादी संवैधानिक अधिकारों का हनन है|

आश्चर्य की बात यह है कि इस ग़लत कदम के लिए क्लब के पत्रकारों के बीच गुटबाजी व सीमापार से अलगाववादी तत्वों से असुरक्षा जैसे बहानेबाजी की अनुचित आड़ ली गयी| पत्रकारों के साथ इस बदसलूकी व बलपूर्वक कार्रवाई से प्रदेश की छवि पर विपरीत असर पड़ेगा|

हैरत कि बात है कि आंतरिक मामलों में सरकारी प्रशासनिक हस्तक्षेप ऐसे वक्त किया गया, जब कश्मीर प्रेस क्लब के पंजीकरण का नवीनीकरण प्रमाणपत्र मात्र एक सप्ताह पूर्व ही क्लब पदाधिकारियों को सौंपा गया था | गौरतलब है कि क्लब की वर्तमान निर्वाचित प्रबंधन समिति ने अगले माह विधिवत चुनाव की तारीख भी घोषित कर दी थी| संस्थाओं को लोकतांत्रिक व पारदर्शिता से संचालित करने का यही सर्वोत्तम रास्ता होता है|

प्रशासन ने चुनावी प्रक्रिया के बीच में कश्मीर प्रेस क्लब में बड़ी तादाद में हथियारबंद दस्तों को लेकर जबरन कब्ज़ा करना न केवल चुनाव प्रक्रिया को जानबूझकर रोका गया बल्कि प्रशासन द्वारा कुछ स्वयंभू बाहरी लोग जिनका क्लब से नाता तक नहीं हैं, उन्हें परिसर और प्रेस क्लब का चार्ज दे दिया| स्थानीय प्रशासन की यह कार्रवाई न केवल अलोकतांत्रिक व गैरकानूनी है बल्कि प्रेस की स्वतंत्रता का हनन है | सचाई के लिए इस घटनाक्रम की तटस्थ जाँच होनी आवश्यक है|

कोई भी लोकतंत्र एक स्वतंत्र मीडिया की अनुपस्थिति में नहीं चल सकता| जो कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम विगत दिनों मे हुआ, वह सीधे तौर पर पत्रकारों के कामकाज में जबरन हस्तक्षेप करना तथा उन्हें हथियारबंद सुरक्षा बलों, पुलिस व प्रशासनिक रौबदाब का भय दिखाकर दबाव में रखने की कोशिश है| आपसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि राज्य मे प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कश्मीर प्रेस क्लब का रजिस्ट्रेशन व क्लब भूमि व भवन आवंटन तत्काल बहाल किया जाए|

आप उप राज्यपाल के जैसे शीर्ष पद पर आसीन होने के नाते प्रदेश के अभिभावक भी हैं इसलिए यह न्याय के हित मे हमारी अपील है कि निर्वाचित क्लब मैनेजिंग कमेटी के सुपुर्द परिसर को वापस सौंपा जाए| साथ ही निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने मे पैदा की गई बाधाओं को दूर करने के लिए आपके स्तर पर कारगर हस्तक्षेप हो| हम आपसे इस पूरे मामले में विवेकसंगत, न्यायपूर्ण समाधान व व्यक्तिगत सहयोग की पूर्ण अपेक्षा रखते हैं| सादर!

उमाकांत लखेड़ा

उमाकांत लखेड़ा
(अध्यक्ष)

Vinay Kumar

विनय कुमार
(सेक्रेटरी जनरल)